

क्या आप जानते हैं ?

सीडीपीओ के 16% पद खाली

राज्य के 38 जिलों के सभी प्रखंडों में समेकित बाल विकास योजना की 544 परियोजनाएं चल रही हैं। इनके तहत कुल 91,600 आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित हैं। आंकड़े बताते हैं इन योजनाओं की मॉनीटरिंग के शीर्ष अधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के 16% पद रिक्त हैं। यहां बता दें कि कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं की देखरेख संबंधी खानपान की जरूरतों को पूरा करने चुनौती को देखते हुए 2 अक्टूबर 1975 को राज्य के

तीन प्रखंडों में समेकित बाल विकास योजना (आईसीडीएस) की शुरुआत हुई थी। राज्य की आबादी में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की हिस्सेदारी 18.3% (2011 की जनगणना) यानी कुल आबादी का 1.91 करोड़ है। आईसीडीएस केंद्र प्रायोजित 6 योजनाओं- पूरक पोषाहार, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं, 3-6 वर्ष के बच्चों को अनौपचारिक विद्यालय पूर्व शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा का पैकेज है।

समेकित बाल विकास योजना के पदों की वस्तुस्थिति

पद	स्वीकृत	कार्यशील	रिक्त
सीडीपीओ	544	458	15.8%
पर्यवेक्षक	3288	2499	24%
सेविका	91677	85944	6.3%
सहायिका	86337	80178	7.1%

(स्रोत : आईसीडीएस निदेशालय-2015-16, बिहार)